कानपुर, गुरुवार, 7 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 113, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड 20साल की दुश्मनी खत्म करने की तैयारी!....>Pg12

नहर में समाई मजदूरों से भरी बस...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या से उबाल, एनकाउंटर की मांग

बंगाल में फिर सियासी खूनी संघर्ष

मध्यग्राम में देर रात बाइक सवार शूटरों ने बरसाईं गोलियां

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई राजनीतिक हिंसा अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में बुधवार देर रात हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। भाजपा इसे 'टारगेटेड पॉलिटिकल असैसिनेशन' बता रही है, जबकि ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व ने आरोपों को खारिज करते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से की गई। चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी से घर लौट रहे थे, तभी एक संदिग्ध कार ने उनकी गाड़ी को रोका और बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुरुआती जांच में विदेशी ग्लॉक-47एक्स पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से कारतूस, जिंदा गोलियां और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार बरामद की गई है।

हत्या के बाद पूरे मध्यग्राम, दमदम और उत्तर 24 परगना के कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों के 'एनकाउंटर' की मांग की। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भी 'राजनीतिक प्रतिशोध' जारी है।

इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की है। टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, यह एसआईटी आईजी सीआईडी के नेतृत्व में बनाई गई है। बाद में राज्य सीआईडी ने भी आधिकारिक तौर पर जांच अपने हाथ में ले ली। पुलिस ने फिलहाल कई विशेष टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक एंगल पर काम शुरू किया है। हालांकि पुलिस ने टीमों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने कई टीमों' के गठन की पुष्टि की है। जांच के दौरान अब तक तीन स्थानीय हिस्ट्रीशीटरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या में पेशेवर शूटरों या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। कई संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को 'दिल दहला देने वाली और पूर्व नियोजित हत्या' बताया है। उन्होंने दावा किया कि हमलावरों ने कई दिनों तक रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। भाजपा सांसदों और नेताओं ने सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चंद्रनाथ रथ पार्टी की रणनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे और इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया।

वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर हत्या की निंदा की और कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो। टीएमसी नेताओं ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग तक उठाई है।

राज्य में इस हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सियासी माहौल दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में चुनावी हिंसा की पुरानी परंपरा अब और ज्यादा खतरनाक रूप लेती दिख रही है। भाजपा इस घटना को राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश कर रही है, जबकि टीएमसी इसे भाजपा की राजनीतिक बयानबाजी बता रही है।

- विदेशी ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल की आशंका, सीआईडी और एसआईटी जांच में जुटी
- भाजपा ने टीएमसी पर लगाया 'राजनीतिक हत्या' का आरोप ममता ने कहा दोषी को गिरफ्तार करो

रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी थे

चंद्रनाथ रथ पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी थे और पिछले कई वर्षों से शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते थे। भाजपा के भीतर उन्हें संगठनात्मक रणनीति और राजनीतिक समन्वय का अहम चेहरा माना जाता था। हालिया चुनावों में भी उन्होंने भाजपा के चुनावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

विदेशी हथियार क्यों बढ़ा रहे चिंता?

जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या में ग्लॉक-47एक्स जैसे विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। यह हथियार सामान्य अपराधियों के पास आसानी से नहीं पहुंचते। इससे पेशेवर शूटरों और संगठित नेटवर्क की आशंका मजबूत हुई है।

एनकाउंटर की मांग क्यों तेज हुई?

सोशल मीडिया और भाजपा समर्थकों के बीच यह भावना तेजी से उभरी कि पेशेवर हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। कई इलाकों में लोगों ने खुले तौर पर एनकाउंटर की मांग की, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है।

पुलिस जांच में सबसे बड़ी चुनौती क्या?

हमलावर फर्जी नंबर प्लेट, प्रोफेशनल शूटिंग पैटर्न और तेजी से फरार होने की रणनीति अपनाकर आए थे। इससे पुलिस को तकनीकी और फॉरेंसिक जांच पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है।

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का पुराना इतिहास

पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनाव बाद हिंसा के लिए चर्चा में रहा है। सत्ता परिवर्तन या बड़े चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक टकराव अक्सर हिंसक रूप ले लेते हैं।

भाजपा क्यों बता रही 'टारगेटेड किलिंग'?

भाजपा का दावा है कि चंद्रनाथ रथ संगठन की कई संवेदनशील रणनीतियों से जुड़े थे। इसलिए पार्टी इसे सामान्य अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या मान रही है।

चंद्रनाथ की हत्या की टाइमलाइन

8:30 शाम बजे
चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम के लिए निकले

10:15 रात बजे
संदिग्ध वाहन ने उनकी एसयूवी का पीछा शुरू किया

10:30 रात बजे
मध्यग्राम के दोहरिया इलाके के पास गाड़ी रोकी गई

10:31 रात बजे
बाइक सवार शूटरों ने बेहद करीब से फायरिंग की

10:40 रात बजे
घायल हालत में रथ को नर्सिंग होम ले जाया गया

11:00 रात बजे
डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया

गुरुवार सुबह
एसआईटी और बाद में सीआईडी जांच में शामिल हुई

कठेरूवा कांड के मुख्य आरोपी पर प्रशासन का बड़ा प्रहार

बुल्डोजर चला, ग्राम समाज की जमीन खाली

धारा-67 के तहत बेदखली, 1.34 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भी आरोपित

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर । कुछ माह पूर्व चर्चित रहे कठेरूवा कांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ बुधवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर बने अवैध कब्जे पर बुल्डोजर चला दिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर राजस्व एवं प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण ध्वस्त कराया और खाली कराई गई भूमि ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में सौंप दी। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफी देर तक हलचल बनी रही।

प्रकरण तहसील सदर क्षेत्र का है, जहां ग्राम समाज की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई गई थी। जांच में गाटा संख्या 672 रकबा 0.1330 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई। मामले में तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में वाद चलाया गया, जिसमें विपक्षी गणेश शंकर बेड़िया पुत्र रामकरन बेड़िया को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

स्थलीय निरीक्षण, राजस्व अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि संबंधित भूमि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है तथा उस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित किया गया।आदेश के अनुपालन में बुधवार को प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। बुल्डोजर लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और कब्जा हटवाकर पूरी भूमि खाली कराई गई।

तहसीलदार न्यायिक न्यायालय द्वारा जारी आदेश में आरोपी पर 1,34,240 रुपये की क्षतिपूर्ति भी आरोपित की गई है। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित धनराशि की नियमानुसार वसूली की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर वसूली चालान भी जारी किया जाएगा।

ग्राम समाज एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में चिन्हांकन कर नियमानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
विनय द्विवेदी तहसीलदार सदर

गुरुदेव के गीतों की गूंज
उत्साह से मनी टैगोर जयंती

बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में दीप प्रज्ज्वलन, गीत-संगीत और छात्रों की 'एकला चलो रे' ने बांधा समां

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज का वातावरण गुरुवार को पूरी तरह साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक उत्साह से सराबोर नजर आया। विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और प्रस्तुति से गुरुदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन, पुष्पार्पण और मंगलाचरण के साथ हुआ। मंच को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे आयोजन में विद्यार्थियों के भीतर विशेष उत्साह दिखाई

दिया। कार्यक्रम में कक्षा 7-सी की छात्रा अर्पिता ने अंग्रेजी भाषा में प्रभावशाली भाषण देकर गुरुदेव टैगोर के साहित्य, शिक्षा और मानवता के विचारों को बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया।

इसके बाद कक्षा 8 के छात्र अस्तित्व ने गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत एकला चले रो... भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया। गीत की प्रस्तुति ने उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों को भावविभोर कर दिया। वहीं कक्षा 7-ए के छात्र आकर्ष ने हिंदी भाषा में प्रेरणादायी संबोधन देते हुए गुरुदेव के आदर्शों और उनके राष्ट्रनिर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला।समारोह के दौरान विद्यालय परिसर तालियों की गूंज से बार-बार उत्साहित होता रहा। कार्यक्रम का समापन वन्दे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ भाग लिया। विद्यालय की उपप्रधानाचार्या एवं समस्त शिक्षकगणों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में साहित्य, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं।

साथ ही विद्यार्थियों को गुरुदेव टैगोर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया

नहर में समाई मजदूरों से भरी बस, डंपर से भिड़ंत के बाद चीख-पुकार का मंजर

क्रेन और हाइड्रा से एक घंटे बाद निकाली गई बस, हाईवे पर 10 किमी लंबा जाम

बिधनू क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मजदूरों से भरी एक प्राइवेट बस डंपर से भिड़ने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नहर में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में बस पानी से भरी करीब 10 फीट गहरी नहर में समा गई। बस में सवार मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। कई मजदूर सीटों और लोहे के ढांचे के बीच फंस गए, जबकि कुछ पानी में डूबती बस से बाहर निकलने के लिए जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए।

हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में उतरकर बस के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ मजदूर खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाले गए, जबकि कई को बस का दरवाजा तोड़कर सुरक्षित निकाला गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी 21 मजदूर रानियां स्थित एक फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस सड़क किनारे बने ढलान से फिसलती हुई नहर में जा गिरी।

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। कई ग्रामीण रस्सियां लेकर पहुंचे और बस के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने लगे। कुछ लोगों ने अपने निजी वाहनों से भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय बस के अंदर बैठे मजदूर जोर-जोर से मदद की गुहार लगा रहे थे। कई मजदूरों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

सूचना मिलते ही बिधनू पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। राहत और बचाव अभियान घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव और सीएफओ दीपक शर्मा की निगरानी में चलाया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पांच एंबुलेंस तैनात की गई थीं। घायलों को तत्काल बिधनू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। घायल मजदूरों के परिजन सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचने लगे। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश मजदूरों को चोटें आई हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

नहर में गिरी बस को बाहर निकालना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। बस आधी पानी में डूबी हुई थी और उसका अगला हिस्सा कीचड़ में धंस गया था। इसके बाद एनएचएआई की क्रेन और दो हाइड्रा मशीनों को मौके पर बुलाया गया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान पुलिस ने हाईवे पर यातायात रोक दिया था। हादसे के कारण कानपुर-सागर हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। हमीरपुर की ओर पतारा तक और कानपुर की ओर रमईपुर तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम रहा। कई यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में बस हटाए जाने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य कराया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण खोना सामने आया है। डंपर चालक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर भारी वाहनों की गति नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया। ग्रामीणों ने नहर किनारे मजबूत बैरिकेडिंग लगाने और हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की मांग भी उठाई है।

21 मजदूर घायल एक की हालत गंभीर

सुबह करीब 7:00 बजे – मजदूरों से भरी प्राइवेट बस रानियां फैक्ट्री के लिए रवाना हुई।

करीब 7:30 बजे – बिधनू क्षेत्र में सामने से आ रहे डंपर से बस की जोरदार टक्कर हुई।

7:32 बजे – अनियंत्रित बस सड़क किनारे नहर में जा गिरी।

7:35 बजे – स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी।

7:45 बजे – पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं।

8:00 बजे तक – सभी 21 मजदूरों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

8:15 बजे – घायलों को बिधनू सीएचसी भेजा गया, एक घायल जिला अस्पताल रेफर।

8:30 बजे – एनएचएआई की क्रेन और हाइड्रा मशीनों से बस निकालने का अभियान शुरू।

करीब 9:30 बजे – बस को नहर से बाहर निकाला गया और यातायात बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

- बस में कुल 21 मजदूर सवार थे।
- सभी मजदूर रानियां स्थित फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे।
- डंपर से भिड़ंत के बाद बस करीब 10 फीट गहरी नहर में गिरी।
- स्थानीय लोगों ने सबसे पहले राहत अभियान शुरू किया।
- पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शीशे तोड़कर मजदूरों को बाहर निकाला।
- एक घायल मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया।
- एनएचएआई की क्रेन और दो हाइड्रा मशीनों से बस बाहर निकाली गई।
- हादसे के कारण हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।
- पुलिस तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह मान रही है।
- सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच जारी है।

सोशल मीडिया पर बच्चे को धमकियां
मां ने साइबर सेल से लगाई गुहार

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। शहर में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से परेशान किए जाने की शिकायत साइबर सुरक्षा अधिकारियों से की है। पीड़िता रामरती (बदला हुआ नाम) के अनुसार, पिछले कुछ समय से उनके बच्चे को अलग-अलग मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

आपत्तिजनक संदेश और ब्लैकमेलिंग से बच्चा तनाव में, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

शिकायत में बताया गया कि अज्ञात लोग बच्चे को आपत्तिजनक संदेश भेज रहे हैं और उस पर अनचाही मांगें मानने का दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर झूठे आरोप लगाने और बदनाम करने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री बनाकर उसके परिचितों में प्रसारित करने की बात भी सामने आई है।

इन घटनाओं से बच्चा गहरे मानसिक तनाव में पहुंच गया है।मामले को लेकर अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतर्क नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने बच्चों से खुलकर संवाद बनाए रखने और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना देने की अपील की। पीड़िता ने साइबर सेल से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

डीबीएस कॉलेज में 'कैशलेस चिकित्सा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

उच्च शिक्षा मंत्री बोले— 1 लाख 25 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। डीबीएस कॉलेज, कानपुर में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल कैशलेस चिकित्सा विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना से उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत 1 लाख 25 हजार से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शिक्षक और स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत समाज का आधार होती है, इसलिए सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की है।

कार्यक्रम में डीबीएस कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सचिव इंजीनियर गोविंद स्वरूप ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा को तकनीक, रोजगार और संस्कार से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएं अब केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा और कैशलेस चिकित्सा योजना की सराहना की।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के सहयोग से विश्वविद्यालय ने नैक में ए++ ग्रेड प्राप्त किया है तथा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी स्थान बनाया है।

कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पाण्डेय ने उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है और कई संस्थानों ने ए+ तथा ए++ ग्रेड हासिल किए हैं।

कार्यक्रम के दौरान डीबीएस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की वरिष्ठ शिक्षिका डॉ. रश्मि दुबे की पुस्तक इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन तथा भौतिक विज्ञान विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. के.के. श्रीवास्तव की व्यक्तित्व विकास पर आधारित पुस्तक आधार का विमोचन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया।

इस अवसर पर पूर्व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री एवं विधायक नीलिमा कटियार, डॉ. अरुणेश अवस्थी, डॉ. हिना अफसर, डॉ. संध्या पाण्डेय, डॉ. ओ.पी. प्रजापति, डॉ. नवीन गुप्ता, डॉ. झांकेश्वर तिवारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षाविद, प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. इन्द्राणी दुबे ने किया।

हाईकोर्ट सख्त: गोविन्द नगर के पार्क में अवैध निर्माण पर जताया आश्चर्य

» पार्कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के दिए निर्देश, दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। गोविन्द नगर के ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क में अवैध निर्माण एवं मंदिर निर्माण के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पार्क, खेल मैदान और सार्वजनिक खुली भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा इन्हें केवल आमजन के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

मामले में याचिकाकर्ता भाजपा नेता प्रकाश वीर आर्य की ओर से अधिवक्ता आदितेन्द्र सिंह एवं चंदन कुमार सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नगर निगम द्वारा आंशिक तोड़फोड़ की कार्रवाई किए जाने के बावजूद पार्क को अब तक उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया गया है।

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने पार्क में हुए निर्माण कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि जिस भूमि को पार्क एवं खेल मैदान के रूप में चिन्हित किया गया हो, वहां आखिर किस परिस्थिति में निर्माण कार्य कराया गया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक पार्कों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए तथा अवैध कब्जों को हटाकर उन्हें पुनः जनता के उपयोग के लिए बहाल किया जाए।

याचिकाकर्ता प्रकाश वीर आर्य ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर को विस्तृत प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। पत्र में पार्क में अवैध रूप से बने कंक्रीट ढांचों एवं इंटरलॉकिंग को हटाने, पार्क को मूल स्वरूप में बहाल करने, पुनः मूर्ति स्थापना एवं नए कब्जों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कथित भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा नगर निगम एवं केडीए अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई गई है।

खंडपीठ ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को आदेश की प्रति नगर आयुक्त एवं केडीए उपाध्यक्ष को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो शहर के अन्य पार्क भी अवैध कब्जों की भेंट चढ़ सकते हैं।

सम्पादकीय

घटनाओं पर राजनीति अस्वीकार्य

गाहे-बगाहे पंजाब में शांति भंग करने के अनेक कुत्सित प्रयास होते नजर आए हैं। सीमा पार से पंजाब का सुख-चैन छीनने के षड?यंत्र काले दौर से लेकर अब तक रुके नहीं हैं। नशे और बेरोजगारी को हथियार बनाकर भटके युवाओं को इन साजिशों का हथियार बनाने के मामले भी उजागर हुए हैं। पंजाब में हाल ही में दो धमाके हुए, पहला जालंधर में बीएसएफ चौकी के बाहर और दूसरा अमृतसर में सेना की छावनी के पास हुआ। सेना और सुरक्षा बलों को लक्षित इन हमलों के घातक मंसूबों को समझा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समय और लक्ष्य के लिहाज से इतने करीबी हमलों के निहितार्थ समझना कठिन नहीं है कि ये महज सामान्य मामले नहीं थे। अब भले ही इन धमाकों की तीव्रता कम रही हो,लेकिन इनमें गंभीर रणनीतिक चेतावनी छिपी है। वह ये कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों की हिफाजत को आंका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा सैन्य क्षेत्र के पास हुए धमाकों में विस्फोटक उपकरण यानी आईडीपी के इस्तेमाल की पुष्टि करना, खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। निस्संदेह, ये महज आकस्मिक घटनाएं मात्र नहीं हैं। ये सुनियोजित तरीके व जासूसी के जरिये रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास की कमजोर कड़ियों को तलाशने की कुत्सित कोशिश है। अब चाहे इन आतंकी गतिविधियों के तार स्थानीय साजिश से जुड़े हों या फिर सीमा पार से साजिश को अंजाम दिया गया हो, कह सकते हैं कि मिलाजुला षड?यंत्र हो, मगर तौर-तरीका स्पष्ट है। हालांकि, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लाइन के अनुरूप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका दोष भाजपा पर मढ़ा है। वहीं भाजपा आप सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह राज्य को सुरक्षा देने में विफल रही है। बहरहाल, भले ही आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल नेताओं को राजनीतिक लाभ-हानि के गणित के अनुरूप लगता हो, मगर राज्य की सुरक्षा के नजरिये से अदूरदर्शी कदम ही कहा जाएगा।यह विडंबना ही है कि पंजाब के राजनेता अतीत के स्याह दौर की घातकता से कोई सबक नहीं सीखते हैं। राजनेताओं की संकीर्णता और दूरगामी प्रभावों को नजरअंदाज करके की गई बयानबाजी ही चिंगारी को आग बनाने का काम करती है। जिसकी कीमत दशकों तक पंजाब के लोगों व राज्य की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। यह सामान्य तथ्य है कि कि जब भी इस संवेदनशील व सीमावर्ती राज्य पर कोई सुरक्षा संकट पैदा हो, उसके लिये राजनीतिक भेदभाव भुलाकर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। टकराव की राजनीति से राज्य का अहित ही होगा। निस्संदेह, पंजाब का अतीत इस मामूली अशांति के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील होने की जरूरत बताता है। दशकों तक पंजाब ने सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों हेतु देशव्यापी ख्याति अर्जित की है। लेकिन हाल की घटनाओं ने हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया ही है। यह गंभीर मसला है कि इस सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में दस दिनों के भीतर तीन सुनियोजित व उच्च तकनीक से लैस विस्फोट हुए हैं।

ये धमाके सभी पक्षों की मेहनत से अर्जित साख को धूमिल करने के जोखिम को बढ़ाते हैं। सवाल मात्र यही नहीं है कि इन धमाकों के लिये कौन जिम्मेदार है। प्रश्न यह भी है कि क्या इन धमाकों के बाबत खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया है? या फिर मिली हुई खुफिया सूचनाओं के आधार पर समन्वित प्रतिक्रिया देने में कहीं चूक हुई है? वास्तव में वक्त की सबसे बड़ी जरूरत इस बात को लेकर है कि हम ऐसी किसी भी चुनौती को लेकर एक समन्वित प्रतिक्रिया दें।

तेजाब और पितृसत्ता के बीच संघर्ष करती स्त्री

के.एस तोमर

एसिड अटैक मानवता के मुंह पर वह तमाचा है, जहां सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाएं एक साथ दम तोड़ती दिखाई देती हैं। ऐसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज की चेतना और नैतिकता को.एसिड अटैक मानवता के मुंह पर वह तमाचा है, जहां सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाएं एक साथ दम तोड़ती दिखाई देती हैं। ऐसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज की चेतना और नैतिकता को कठघरे में खड़ा कर देते हैं।

हाल ही में देश के शीर्ष न्यायालय ने 'शाहीन मलिक बनाम भारत संघ' मामले में एसिड अटैक के संबंध में मौजूदा कानूनों के तहत तेजाब हमलों से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने माना कि ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित दंड पर्याप्त नहीं हैं तथा कई पीड़ित अब भी उचित कानूनी पहचान और सहायता से वंचित हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की भी समीक्षा की। अदालत ने पाया कि अधिनियम की वर्तमान अनुसूची में तेजाब हमले के पीड़ितों को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखा गया है जो 'एसिड या इसी तरह के संहारक पदार्थ फेंकने से हुए हिंसक हमलों के कारण विकृत हो गए हैं।' न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुसूची में संशोधन कर ऐसे मामलों को शामिल करने पर विचार करने को कहा।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, 'यदि इस संशोधन को अधिसूचित किया जाता है तो हम इसकी सराहना करेंगे।' यही नहीं पीठ ने तेजाब की सहज उपलब्धता और उसकी अवैध बिक्री पर भी गंभीर चिंता जताई और कहा कि अवैध रूप से तेजाब बेचने वाले विक्रेताओं को जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा ऐसे मामलों में उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि दायित्व केवल हमलावर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान अपराधियों पर कठोर आर्थिक दंड लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई। अदालत ने टिप्पणी की, 'हमलावर की संपत्ति, जिसमें संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा भी शामिल है, क्यों न जब्त की जाए? हम आत्मसम्मान आदि की बात करते हैं... तो आरोपी को क्यों नहीं भुगतना चाहिए एसिड अटैक मानवता के मुंह पर वह तमाचा है, जहां सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाएं एक साथ दम तोड़ती दिखाई देती हैं। ऐसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज की चेतना और नैतिकता को कठघरे में खड़ा कर देते हैं। विशेष रूप से वे लोग भी प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं, जो इस हिंसा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। बिना किसी अपराध के जीवनभर असहनीय पीड़ा सहना केवल शारीरिक या मानसिक यातना भर नहीं है। यह उस धीमे ज़हर की तरह है, जिसमें पीड़िता हर दिन जीते हुए स्वयं को अपराधबोध, उपेक्षा और सामाजिक असहजता के बीच घिरा हुआ पाती है। विडंबना यह है कि तेजाब का प्रभाव केवल शरीर को नहीं जलाता, बल्कि वह व्यक्ति के आत्मविश्वास, संबंधों और जीवन के प्रति विश्वास को भी भीतर तक झुलसा देता है। यदि हम यह सोचते हैं कि ऐसी कुंठित मानसिकता केवल भारत तक सीमित है, तो यह हमारी गंभीर भूल होगी। स्त्री को अस्वीकार किए जाने, नियंत्रण खो देने या आहत अहंकार के प्रतिशोध में हिंसा का शिकार बनाना दरअसल संपूर्ण विश्व की एक सामाजिक बीमारी है। पुरुष अक्सर स्त्री की 'न' को स्वीकार नहीं कर पाता। जब उसका अहंकार घायल होता है, तब वह शक्ति, भय, हिंसा या नियंत्रण के माध्यम से स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और जब वह ऐसा करने में असफल होता है, तब कई बार प्रतिशोध सबसे क्रूर रूप में सामने आता है।नारीवादी चिंतक बेल हुक्स पितृसत्ता को ऐसी व्यवस्था मानती हैं, जो पुरुष को यह विश्वास दिलाती है कि प्रभुत्व उसका स्वाभाविक अधिकार है। वहीं मनोवैज्ञानिक लंडी बैनक्रॉफ्ट अपनी पुस्तक 'व्हाय डज़ ही डू दैट' में लिखते है।

'सरहदी राज्य' के नारे संग चुनावी रणनीति

पश्चिम बंगाल और असम जैसे 'बॉर्डर स्टेट्स' के बाद अब भाजपा पंजाब के लिए 'सरहदी राज्य का नारा' देने की तैयारी में है। भाजपा मुख्यालय में बंगाल-असम जीत के जश्न के दौरान भी इसकी झलक मिली।बंगाल जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पैनी नजर अब पंजाब पर है। अकाली दल के साथ पहले भी पंजाब में सत्ता का स्वाद चख चुकी भाजपा अब यहां 'एकला चलो' की रणनीति पर काम कर रही है।

बेशक पंजाब के सियासी शतरंज में शह-मात के खेल में गोटी फिट करना टेढ़ी खीर है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम जैसे 'बॉर्डर स्टेट्स' के बाद अब वह पंजाब के लिए 'सरहदी राज्य का नारा' देने की तैयारी में है। भाजपा मुख्यालय में बंगाल-असम जीत के जश्न के दौरान भी इसकी झलक मिली। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ इस जश्न में अनेक सिख नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान इन लोगों ने खूब नारे लगाए।पंजाब को लेकर भाजपा इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि उसे यकीन है कि फिर से एकजुट हो रहे 'इंडिया' गठबंधन की एकता यहां नहीं रहेगी। इस राज्य में कांग्रेस तो अकेले लड़ेगी ही, आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में वापसी की अलग से पूरी कोशिश करेगी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि भाजपा के विजय रथ को पंजाब रोकेगा। अकाली दल अपनी तैयारी कर ही रहा है। कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों की भी चुनाव में भूमिका होती है। ऐसे में भाजपा बिखरे विपक्ष का फायदा उठाएगी। इसी तरह का लाभ उसे बंगाल और असम में भी मिला है। चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये आखिरी विजय है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। आप से भाजपा में गए राज्यसभा सदस्यों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने

पंजाबियों की इन सीटों को लूटा है। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया में आरोप लगाया कि भाजपा ने सौ सीटों की लूट की है। इसी तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव में सीट चोरी का आरोप लगाया है। वह मोदी के खिलाफ अक्सर ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं।इस बीच, भाजपा नेताओं ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को दोहराने की उम्मीद जताई है। भाजपा के रणनीतिकार सरहदी राज्य की सुरक्षा, नशा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वैसे पंजाब के अलावा अगले साल गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हैं, लेकिन भाजपा के लिए पंजाब प्रमुख है। पार्टी यहां अपना वर्चस्व बनाकर एक संदेश देने की कोशिश में है।अन्य राज्यों में भी भाजपा की तैयारी जोरों पर है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इन राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकों में भाग ले चुके नबीन अब पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन राज्यों के साथ ही भाजपा उत्तराखंड के लिए भी जोरशोर से जुट गयी है। उत्तराखंड में जहां चीन और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, वहीं गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान सीमा से सटा है। पंजाब भी पाकिस्तान सीमा से सटा है। मणिपुर राज्य भी म्यांमार से सटा है और यहां कुछ समय तक अशांति रही। हालांकि अभी भी इस सरहदी राज्य में हिंसा की छिटपुट वारदातें हो रही हैं। दो समुदायों के बीच संघर्ष को सुलझाने का काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। मणिपुर को लेकर कांग्रेस अनेक बार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती रही है। काबिल-ए-गौर है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आप और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। यहां उसने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। असम में सत्तारूढ़ राजग दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सत्ता में लौटा है। राजग ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की जबकि उसके सहयोगी दलों- बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) को 10-10 सीट पर जीत मिली है।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...

फुटकर नहीं तो पांच रुपये गए!

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से यात्रियों से पांच रुपये ज्यादा लेने के आरोप सामने आए हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के दौरान यदि उनके पास खुले रुपये नहीं होते तो काउंटर कर्मचारी पांच रुपये वापस नहीं करते। ट्रेन छूटने की जल्दबाजी में लोग मजबूरी में रुपये छोड़ने को विवश हो जाते हैं।

बताया जा रहा है कि कासगंज से चलकर अनवरगंज जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 12ः55 बजे बिल्हौर स्टेशन पहुंचती है। कानपुर तक का टिकट 35 रुपये का है। आरोप है कि यदि यात्री 50 रुपये देता है तो उसे 15 रुपये लौटाने के बजाय केवल 10 रुपये वापस किए जाते हैं। विरोध करने पर कर्मचारियों की ओर से टूटे पैसे लेकर आओ कह दिया जाता है।

यात्रियों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों लोग इस रूट पर सफर करते हैं। ऐसे में हर यात्री से पांच रुपये रोके जाने पर बड़ी रकम का खेल हो सकता है। कई बार इस बात को लेकर यात्रियों और कर्मचारियों के बीच बहस भी हो चुकी है। बुधवार को मामला उस समय चर्चा में आया जब बिल्हौर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री किसी काम से कानपुर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई, जिसके बाद वह ट्रेन से सफर करने स्टेशन पहुंचे। उनके साथ दो अन्य अधिवक्ता भी थे। तीन टिकटों का किराया 105 रुपये बनता था, लेकिन आरोप है कि उनसे 110 रुपये ले लिए गए। अधिवक्ताओं ने इसका विरोध भी जताया।

एक अधिवक्ता ने बताया कि मामला

- बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर टिकट में पांच रुपये का खेल
- छुट्टे के नाम पर यात्रियों से ज्यादा वसूली के आरोप
- अधिवक्ता बोले— यह मनमानी बंद हो

यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ने से खुले रुपये की समस्या आती है। सबसे बेहतर तरीका है कि यात्री ऑनलाइन पेमेंट करें। रेलवे स्टेशन पर इसकी सुविधा उपलब्ध है।

- संजीव शर्मा, सीनियर डीसीएम इज्जतनगर मंडल

रेलवे अधिकारी क्रॉस चेकिंग करें तो पकड़ में आएगा खेल

यात्रियों का आरोप है कि टिकट काउंटर पर छुट्टे रुपये के नाम पर रोजाना पांच-पांच रुपये रोके जा रहे हैं। कोई ज्यादा विरोध करता है टिकट के हिसाब से उसके रूपये काटे जाते हैं।लोगों का कहना है कि यदि रेलवे अधिकारी अचानक क्रॉस चेकिंग करें और टिकट बिक्री का हिसाब मिलाएं तो पूरा मामला सामने आ सकता है।

सिर्फ पांच रुपये का नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मनमानी का है। उनका कहना था कि टिकट बांटने वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में रेलवे प्रशासन से शिकायत की जाएगी। स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी

दावा किया कि उनके पांच-पांच रुपये फंस गए। लोगों का कहना है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी में अधिकतर यात्री विवाद नहीं करते और अतिरिक्त रकम छोड़कर चले जाते हैं। यात्रियों ने कहा है कि रेलवे प्रशासन से टिकट काउंटर की व्यवस्था सुधारने और छुट्टे रुपये की व्यवस्था रखे, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त भुगतान से बचाया जा सके।

2014 हत्याकांड के पीड़ित को धमकी, पांच लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। गोविंद नगर के चर्चित हत्याकांड से जुड़े एक पीड़ित परिवार को फिर से धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष से जुड़े लोगों ने उसे रास्ते में रोककर केस वापस लेने और अदालत में पैरवी बंद करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर पांच लाख रुपये की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया कि वर्ष 2014 में गोविंद नगर क्षेत्र में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में कई आरोपियों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिली थी। मुख्य आरोपी राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अप्रैल माह में चौबेपुर क्षेत्र स्थित डेरी फार्म से लौट रहा था। इसी दौरान बाबा रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उससे कहा कि चल रहे मुकदमों की पैरवी बंद कर दे और अदालत में ज्यादा सक्रियता न दिखाए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने जमानत में खर्च होने की बात कहते हुए अगली तारीख तक पांच लाख रुपये देने का दबाव बनाया। रुपये न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान और भूमिका स्पष्ट की जा रही है।

- केस की पैरवी छोड़ने का बनाया दबाव
- पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच

पंचायत बैठक में विकास से लेकर किसानों के मुद्दों तक गूंजे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर ब्लॉक के अम्बेडकर सभागार में बुधवार को आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में गांवों के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया, जबकि कुछ विभागीय व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठे।

बैठक का शुभारंभ वंदेमातरम के साथ किया गया। ब्लॉक प्रमुख मनोरमा कठेरिया और बीडीओ नेम चंद्र ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांवों में चल रही योजनाओं की निगरानी मजबूत करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि विकास कार्य प्राथमिकता तय कर कराए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक गांवों को लाभ मिल सके। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों

में साफ-सफाई, सड़क, पेयजल और पेंशन योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। बीडीओ ने प्रधानों से पात्र लोगों तक वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ पहुंचाने में सहयोग मांगा। राशन वितरण व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई। कुछ पंचायत प्रतिनिधियों ने श्रम विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर आपत्ति जताई। इसको लेकर सदन में नाराजगी दिखाई गई और निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सहकारी संघ बिल्हौर के अध्यक्ष गिरीश वर्मा ने समितियों में खाद बिक्री की सीमा तय किए जाने का विरोध करते हुए इसे किसानों के हितों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे खेती-किसानी प्रभावित हो सकती है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य गगन ठाकुर, भाजपा नेता ज़िला महामंत्री जेपी कटियार,विक्रम मिश्रा, ग्राम प्रधान मकनपुर मजाहिर हुसैन जाफरी,डॉ. नीरज पटेल, दीपक श्रीवास्तव, सीतेंद्र कटियार, सिपाहीलाल कठेरिया, अमित यादव और सौरभ यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।

संदिग्ध हालात में किसान ने दी जान, कमरे में मिला शव

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कुरेह गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किसान का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कुरेह निवासी बृजभान उर्फ बड़े लल्ला (42) खेती कर परिवार चलाते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। ग्रामीणों के अनुसार वह सामान्य स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। बताया गया कि बुधवार रात वह परिवार के साथ सामान्य तरीके से रहे। सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर घरवालों ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थाना प्रभारी जितेंद्र राजपूत ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

बंगाल की जीत से उत्साहित भाजपा लेकिन यूपी की सियासत का गणित अलग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

जाति, महिला और सवर्ण वोटर बनेंगे 2027 के सबसे बड़े फैक्टर!

लखनऊ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भारतीय जनता पार्टी भले ही उत्साहित दिखाई दे रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन बंगाल से पूरी तरह अलग मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल का चुनावी माहौल, सामाजिक संरचना और मुद्दे उत्तर प्रदेश से मेल नहीं खाते। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी होगा, इस पर अभी से राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कानून व्यवस्था, दंगा और बड़े सांप्रदायिक टकराव जैसे मुद्दे पहले की तुलना में काफी हद तक नियंत्रित रहे हैं, जबकि बंगाल लगातार राजनीतिक हिंसा और टकराव की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। यही वजह है कि यूपी में चुनावी मुद्दों का केंद्र विकास, सामाजिक समीकरण और जातीय संतुलन पर अधिक केंद्रित दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो उत्तर प्रदेश में जातिगत ध्रुवीकरण अब भी चुनावी राजनीति का सबसे मजबूत आधार बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने ÷पीडीए÷ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को केंद्र में रखकर अपना अभियान तेज किया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार और संगठन में बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी देकर सामाजिक संतुलन साधने में जुटी हुई है। ऐसे में 2027 में असली बढ़त किसे मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

इधर पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटरों की भूमिका बेहद निर्णायक रूप में सामने आई है। बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में महिला मतदाताओं ने संगठित तरीके से मतदान कर सत्ता की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में भी महिला सुरक्षा, उज्ज्वला योजना, राशन, आवास और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का असर सीधे महिला वोट बैंक पर पड़ता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों ने भी महिला वोटरों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक और बड़ा वर्ग सवर्ण मतदाता का है, जो यूपी की राजनीति में लगभग 21 से 22 प्रतिशत तक प्रभाव रखता है। यूजीसी और आरक्षण जैसे मुद्दों के बाद सवर्ण वर्ग को लेकर भी सभी दल सक्रिय दिखाई देद रहे हैं। भाजपा परंपरागत रूप से इस वर्ग की पहली पसंद मानी जाती रही है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में अन्य दल भी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल हिंदुत्व या विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जातीय संतुलन, महिला वोट बैंक और सवर्ण वर्ग की नाराजगी या समर्थन ही सत्ता की चाबी तय करेगा। बंगाल की जीत भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दे सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात कहीं अधिक जटिल और बहुस्तरीय मानी जा रही है।

यूपी में डिजिटल जनगणना शुरू, अब लोग खुद भर सकेंगे अपना पूरा ब्योरा

» 21 मई तक चलेगी स्वगणना प्रक्रिया, 22 मई से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

» 34 सवालों के जवाब देने पर मिलेगी विशेष आईडी, जनगणना में लगेंगे पांच लाख कर्मचारी

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। इस बार लोग खुद अपनी जनगणना कर सकेंगे। स्वगणना की यह प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी।

इसके बाद 22 मई से प्रगणक घर-घर जाकर आंकड़ों का सत्यापन करेंगे और जिन लोगों ने स्वगणना नहीं की होगी, उनका पूरा विवरण दर्ज करेंगे।

जनगणना विभाग के अनुसार इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में कराई जा रही है। स्वगणना के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जहां नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।इस दौरान लोगों को कुल 34 सवालों के जवाब देने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एक विशेष स्वगणना आईडी यानी एसई आईडी जारी की जाएगी। बाद में प्रगणक घर पहुंचकर इसी आईडी के जरिए जानकारी का सत्यापन करेंगे।22 मई से शुरू होने वाला जनगणना का पहला आधिकारिक चरण 20 जून तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक मकानों और परिवारों की गणना करेंगे। विभाग के मुताबिक दूसरे चरण की जनगणना अगले वर्ष कराई जाएगी।

जनगणना नियमों के अनुसार एक साथ रहने और एक ही रसोई में भोजन करने वाले लोगों को एक परिवार माना जाएगा। साझा रसोई परिवार की पहचान का मुख्य आधार होगी।

वहीं मकान उसी को माना जाएगा, जिसका अलग मुख्य प्रवेश द्वार हो और जो आंगन, सड़क या सीढ़ियों से अलग हो।प्रदेश में जनगणना कार्य के लिए लगभग पांच लाख कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसमें रिजर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। बड़े स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है, जबकि शेष कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अब तेजी लाई जा रही है। विभाग की ओर से कर्मचारियों को लगातार संदेश भेजकर प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए जा रहे हैं।इधर, राज्य सरकार की नई तबादला नीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जनगणना में लगे कर्मचारियों को तबादला प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है।तबादला सत्र की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई है, जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारी 22 मई से जनगणना ड्यूटी में लगाए गए हैं। ऐसे में बीच में तबादला होने की स्थिति में जनगणना कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।जनगणना विभाग का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था के जरिए प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और अधिक सटीक बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रदेश की जनसंख्या और सामाजिक आंकड़ों का सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

भगवान परशुराम जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब

» पूर्व विधायक आदित्य पाण्डेय ने अतिथियों का किया सम्मान, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी स्मृति चिन्ह भेंट

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फतेहपुर । फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की जहानाबाद विधानसभा में भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक आदित्य पाण्डेय द्वारा विशाल शोभायात्रा एवं भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, युवाओं एवं महिलाओं ने भाग लेकर भगवान परशुराम के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पिछड़ावर्ग आयोग भारत सरकार की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान परशुराम के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और धर्म रक्षा के प्रतीक हैं।

कार्यक्रम में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, विधायक सरोज कुरील, विधायक अभिजीत सिंह सांगा तथा अयोध्या धाम से पधारे महंत शाश्वत जी महाराज ने भी अपने विचार एवं आशीर्वचन देकर जनसमूह को संबोधित किया।

पूर्व विधायक आदित्य पाण्डेय ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं समाजसेवियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में विजय चौहान, लक्ष्मीकांत तिवारी, संजय कटियार, शिवसागर शुक्ला, राज किशोर शुक्ला, विप्र त्रिवेदी, रामजी मिश्रा, राजेश पांडेय, अनुराग मिश्रा एवं मनोज शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान मंच से सामाजिक समरसता,

सांस्कृतिक एकता एवं सनातन परंपरा को मजबूत करने का संदेश दिया गया। जनसभा में भारी भीड़ और लोगों के उत्साह ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया।

एचपीसीएल डिपो पर चालक की मौत के बाद फूटा गुस्सा, टैंकर चालकों ने किया चक्का जाम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के गोगूमऊ स्थित एचपीसीएल डिपो बुधवार को उस समय तनाव और आक्रोश का केंद्र बन गया, जब टैंकर चालक अर्जुन अवस्थी की मौत के बाद साथी चालकों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित चालकों ने डिपो के मुख्य गेट पर टैंकर आड़े-तिरछे खड़े कर चक्का जाम कर दिया और कार्य बहिष्कार करते हुए जमकर हंगामा काटा। हालात ऐसे बने कि प्रतिदिन 200 से 250 टैंकरों की लोडिंग करने वाला डिपो पूरे दिन पूरी तरह ठप रहा और एक भी टैंकर लोड नहीं हो सका।

डिपो गेट पर शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा, 60 लाख मुआवजे की उठाई मांग

पत्नी का आरोप, उधारी के रुपये मांगने पर बेल्टों से पीटकर टैंकर चढ़ाकर की गई हत्या

जानकारी के मुताबिक भरत रोड लाइंस का चालक अर्जुन अवस्थी (45) मंगलवार को डिपो के बाहर पार्किंग क्षेत्र में टैंकर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन-फानन में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चालक की मौत की सूचना मिलते ही साथी चालकों में भारी आक्रोश फैल गया। बुधवार सुबह से ही चालकों ने डिपो गेट पर मोर्चा संभाल लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

उधर पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर डिपो पहुंचने के लिए निकले, लेकिन संभावित बवाल को देखते हुए पुलिस ने रायपुर और श्यामपुर गांव के बीच शव वाहन को रोक लिया। इस दौरान माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम करने का प्रयास भी किया, हालांकि पुलिस अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद स्थिति नियंत्रित हो सकी। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद परिजन शव लेकर डिपो गेट पहुंचे और दोपहर करीब 3.25 बजे शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

मृतक की पत्नी शिखा अवस्थी ने ट्रांसपोर्टर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पति ने ट्रांसपोर्टर से अपने उधार के 15 हजार रुपये मांगे थे।

इसी बात से नाराज होकर पहले उनके पति को टैंकर से उतारकर बेल्ट, लात और घूंसों से बेरहमी से पीटा गया, फिर टैंकर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। रोते-बिलखते परिजनों ने 60 लाख रुपये मुआवजा, आठ वर्षीय बेटी की परवरिश तथा शादी का पूरा खर्च उठाने की मांग रखी। डिपो गेट पर घंटों चले हंगामे और वार्ता के बाद ट्रांसपोर्टर की ओर से ढाई लाख रुपये नगद तथा डिपो प्रबंधन की ओर से 20 लाख रुपये सहायता देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए।

सर्पदंश से युवक की हालत गंभीर हैलट रेफर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के चतुर निवादा गांव में 20 वर्षीय दिग्विजय सिंह को जहरीले सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन-फानन में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद पहुंचाया। बताया गया कि दिग्विजय घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी अचानक सर्प ने उन्हें काट लिया। सर्पदंश के बाद युवक की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. शैलेंद्र कुमार ने युवक का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

उमाशंकर मीरा देवी इंटर कॉलेज में मेधावियों का सम्मान, छात्र-छात्राओं का बढ़ाया उत्साह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उमाशंकर मीरा देवी इंटर कॉलेज तिगाई में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानाचार्य रामजी यादव ने विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं माल्यार्पण कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इंटरमीडिएट परीक्षा में अनामिका ने 85 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। दिव्यांशी पाल ने 80 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय तथा प्रिया शर्मा ने 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं हाईस्कूल परीक्षा में अंशिका ने 80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, शिवा ने 79 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय तथा प्रगति ने 77 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया।

विद्यालय के संस्थापक उमाशंकर दीक्षित एवं डॉ. राम शंकर द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में अन्य सफल छात्र-छात्राओं को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रधानाचार्य रामजी यादव ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता विद्यालय, अभिभावकों और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर शिक्षक कपिल पांडे, नंदकिशोर, सुशील, अनीश, शशिकांत, अवधेश शर्मा, विनोद तिवारी, अनिल, पूनम मिश्रा एवं अंकिता सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों ने टॉपर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

सूने घर में झूल गई जिंदगी- विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

» बच्चे की नजर पड़ते ही मचा हड़कंप, एक वर्ष पूर्व मंदिर में हुआ था प्रेम विवाह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के दुवारी गांव में गुरुवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक विवाहिता ने कमरे के अंदर पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दुवारी गांव निवासी नीलम उर्फ नीलू (30) का विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व कानपुर में एक मंदिर में अभिषेक कुमार त्रिवेदी के साथ हुआ था। अभिषेक ऑटो किराए पर चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था, लेकिन आमदनी कम होने के कारण वह तीन दिन पहले नौकरी की तलाश में बनारस चला गया था।बताया गया कि घर में नीलू अकेली रह रही थी। गुरुवार दोपहर उसने कमरे के अंदर फांसी लगा ली। घटना का खुलासा तब हुआ, जब पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा किसी काम से उनके घर पहुंचा। कमरे के अंदर नीलू को फांसी पर झूलता देख उसने शोर मचा दिया। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी परिजनों व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मृतका का देवर अविनाश पनकी से गांव पहुंचा। वहीं गजनेर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है।परिजनों ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने बुधवार को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बीते मंगलवार की दोपहर करीब 12.47 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर से शौचक्रिया के वास्ते निकली थी ।आरोप है कि तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे युवक शिवम् ने उसे दबोच लिया तथा जंगल में ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।शोर शराबा सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पॉस्को समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।आरोपी की तलाश की जा रही है।जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जल्लापुर में नहीं थमा बुखार, दर्जनों और बीमार

» तालाब लबालब, जल निकासी न होने से बढ़ी परेशानी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के जल्लापुर गांव में गंदगी और जलभराव के कारण फैल रही बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव के कठेरिया मोहल्ले में 20 से अधिक लोग बुखार, उल्टी-दस्त और संक्रमण की चपेट में हैं। कई मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं। लगातार बढ़ रही बीमारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।ग्रामीणों के अनुसार मोहल्ले का गंदा पानी गांव के तालाब में जाता है, लेकिन कई वर्षों से तालाब की सफाई और जल निकासी का समुचित प्रबंध नहीं होने से तालाब पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। इससे घरों के बाहर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गंदगी और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के चलते बीमारी तेजी से फैल रही है। बुखार से पीड़ितों में दीपिका (15), सौरभ (5), बलवीर (4), दीपक (10), भूरी (6), रिचा (5), रामजनी (7), विद्या (10), शिवा (12), सौरभ (7), आरुषी (12), गोपाल (15), दिव्या (2) समेत 20 से अधिक लोग शामिल हैं। कई मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीमारी फैलने की सूचना पर बुधवार को मलेरिया निरीक्षक विशाल सिंह टीम के साथ गांव पहुंचे। टीम ने रामजाने, गोविन्द, मानसी, लव, पूजा, बलवीर, गौरव, सरोज और रिया समेत दस लोगों के खून के नमूने लेकर मलेरिया जांच की। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने पर मरीजों को दवाइयां वितरित की गईं। साथ ही जलभराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया गया और लोगों को संक्रामक रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में नियमित सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं राजपुर बीडीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि पंपिंग सेट लगाकर तालाब की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

कुपोषित बच्चों को भेजा गया एनआरसी सेंटर

» आरबीएसके टीम की जांच में सामने आया कुपोषण, समझाने पर परिजन हुए तैयार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक के बनवारीपुर गांव में कुपोषण से जूझ रहे दो बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एनआरसी (न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर) में भर्ती कराया गया।जानकारी के अनुसार बनवारीपुर निवासी सिम्पू कुमार के 4 वर्षीय बच्चे नयन और पायल जन्म से ही कुपोषण की समस्या से ग्रसित थे। एएनएम पारुल की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को डॉ. आशीष मिश्रा आरबीएसके टीम के साथ गांव पहुंचे और दोनों बच्चों की जांच की। जांच में कुपोषण के लक्षण मिलने पर टीम ने परिजनों को एनआरसी सेंटर में भर्ती कराने की सलाह दी। शुरुआत में परिजनों ने बच्चों को भर्ती कराने से इंकार कर दिया। इस पर डॉ. आशीष मिश्रा ने उन्हें समझाया कि एनआरसी सेंटर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का विशेष देखभाल के साथ उपचार और पोषण पुनर्वास किया जाता है। यहां संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी के माध्यम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार किया जाता है। समझाने के बाद परिजन तैयार हुए और दोनों बच्चों को एनआरसी सेंटर में भर्ती कराया गया।

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी

मंडल कार्यसमिति बैठक में बूथ सत्यापन और संगठन मजबूती पर मंथन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात के तत्वावधान में मंडल पुखरायां में आवश्यक मंडल कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सौरभ मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि बूथ सत्यापन अभियान को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक बूथ पर जाकर समिति का सत्यापन किया जाए तथा शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है।

बैठक में भाजपा की जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया।मंडल अध्यक्ष मुकुल पांडे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी और सभी कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की। बैठक में प्रमुख रूप से कुलदीप सचान, डिंपल सचान, स्वतंत्र पासवान, अक्षय त्रिवेदी, ऋषि त्रिपाठी, सचिन सचान, सुरेंद्र द्विवेदी, नरेंद्र साहू, किशन कठेरिया, रवि यादव, प्रमोद त्रिपाठी, अमरेश अग्निहोत्री, रजनी तिवारी, कल्लू सभासद समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एलडीए प्रवर्तन जोन-1 में श्रमिक मौत कांड दबाने का खेल?

जांच रिपोर्ट पर रहस्य, बहाली के बाद फिर मलाईदार तैनाती पर सवाल

» उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के सख्त रुख के बावजूद प्रवर्तन में चरम पर भ्रष्टाचार

» इंजीनियर के निलंबन के बाद फिर वही मलाईदार पोस्टिंग!

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार प्रवर्तन अनुभाग में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं. प्रवर्तन जोन-1 में अवैध निर्माण, संरक्षण और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हुई श्रमिक की मौत का मामला अब सवालों के घेरे में आ गया है। घटना की जांच अपर सचिव सी.पी. त्रिपाठी को सौंपी गई थी, लेकिन महीनों बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। न तो दोषियों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की गई। इससे पूरे मामले को दबाने की आशंका तेज हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक जिस निर्माण स्थल पर हादसा हुआ, वह क्षेत्र प्रवर्तन जोन-1 में तैनात अवर अभियंता विपिन राय के कार्यक्षेत्र में आता है। आरोप है कि बेसमेंट खुदाई वाले निर्माणों में सुरक्षा मानकों की जांच के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद मौके पर कोई प्रभावी निरीक्षण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी के बीच श्रमिक की जान चली गई।

एलडीए के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा अवर अभियंता विपिन राय की तैनाती को लेकर हो रही है। सूत्र बताते हैं कि अवैध निर्माण कराने के आरोप में निलंबित होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश से बहाल हुए विपिन राय ने जुगाड़ तंत्र के दम पर प्रवर्तन जोन-1 में तीसरी बार तैनाती हासिल कर ली। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्रभाव है, जिसके चलते एक ही अधिकारी बार-बार सबसे विवादित और मलाईदार जोन में पहुंच जाता है।स्थानीय लोगों और बिल्डर लॉबी में चर्चा है कि जोन-1 में अवैध निर्माणों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। आरोप यह भी हैं कि नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला निर्माण, बेसमेंट खुदाई और मानचित्र से अलग निर्माण कार्यों को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

'ईमानदार' सुपरवाइजर का वर्षों से कायम जलवा

प्रवर्तन जोन-1 में तैनात सुपरवाइजर वीरेंद्र यादव का नाम भी चर्चाओं में है। सूत्रों का दावा है कि वह कई वर्षों से लगातार इसी जोन में तैनात हैं और क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव बना हुआ है। व्यंग्यात्मक अंदाज में कर्मचारी तक कहते नजर आते हैं कि उनकी ईमानदारी इतनी मजबूत है कि कोई अधिकारी उन्हें इधर से उधर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।

सूत्र बताते हैं कि क्षेत्र में होने वाले अधिकांश निर्माण कार्यों की जमीनी जानकारी सुपरवाइजर स्तर पर रहती है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध निर्माणों की जानकारी जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुंची।

जांच रिपोर्ट पर पर्दा यों?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपर सचिव स्तर की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? यदि जांच पूरी हो चुकी है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि जांच लंबित है तो फिर देरी की वजह क्या है?

एलडीए प्रवर्तन विभाग पहले भी अवैध निर्माणों को संरक्षण देने, सेटिंगबाजी और वसूली के आरोपों को लेकर विवादों में रहा है। श्रमिक की मौत के बाद उम्मीद थी कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक की चुप्पी पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

निर्माण माफियाओं के आगे बेबस एलडीए?

शहर में लगातार अवैध निर्माणों के बढ़ते मामलों ने यह धारणा मजबूत कर दी है कि एलडीए का प्रवर्तन तंत्र निर्माण माफियाओं के सामने पूरी तरह बेबस या फिर सांठगांठ में लिप्त है। नियम सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं, जबकि जमीन पर बेसमेंट खुदाई से लेकर बहुमंजिला अवैध निर्माण तक खुलेआम जारी हैं। अब देखना यह होगा कि श्रमिक मौत कांड की जांच रिपोर्ट कभी सामने आएगी या यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।

स्वराज इंडिया
भ्रष्ट जेई पर कार्यवाही के बावजूद बदस्तूर जारी है
सीलिंग में डीलिंग का अद्भुत खेल
एलडीए प्रवर्तन जोन-5 में सुविधा शुल्क देकर बिल्डरों की चांदी

लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार पर पहले भी स्वराज इंडिया ने किया था खुलासा

मथुरा में पुलिस का बड़ा एनकाउंटर 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश ढेर

डकैती कांड में वांछित बावरिया गिरोह के बदमाशों से सुबह हुई मुठभेड़, एसओजी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी घायल

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

मथुरा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार सुबह मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाश मार गिराए गए। दोनों बदमाश बावरिया गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं और हाल ही में हुई डकैती की वारदात में वांछित थे।मुठभेड़ थाना सुरीर क्षेत्र के टैंटीगांव अंडरपास के पास सुबह करीब पांच बजे हुई। पुलिस के मुताबिक अपाचे बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में राजस्थान निवासी धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्गविजय सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास था और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में गंभीर मुकदमे दर्ज थे।एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि 23 अप्रैल की रात टैंटीगांव में व्यवसायी अजय अग्रवाल के घर हुई डकैती में यही बदमाश शामिल थे।बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे थे और परिवार को बंधक बनाकर करीब 12 लाख रुपये के जेवर और 3.22 लाख रुपये की नकदी लूट ले गए थे। जाते समय बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए थे।

घटना के खुलासे के लिए एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर एसपी देहात और सीओ मांट के नेतृत्व में 17 टीमें गठित की गई थीं। पुलिस ने मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, हापुड़ और राजस्थान तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की थी। लगातार निगरानी के बाद गुरुवार सुबह पुलिस को सफलता मिली।प्रदेश में पिछले चार दिनों के भीतर यह चौथा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले आंबेडकरनगर में चार बच्चों और एक महिला की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने मार गिराया था, जबकि हरदोई में मासूम के अपहरण और हत्या के आरोपी मेहनूर को ढेर किया गया था। इसके अलावा कई जिलों में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।पुलिस अब बावरिया गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और उनसे जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

घंटे की गूंज से चलता है गांव का समय

झंडी राजमहल आज भी निभा रहा सदियों पुरानी परंपरा

शरद मिश्रा /स्वराज इंडिया

लखीमपुर खीरी। आधुनिकता के इस दौर में जहां गांवों की पहचान तेजी से बदल रही है, वहीं झंडी राजमहल आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और सामाजिक सरोकारों को जीवित रखे हुए है। ऐतिहासिक झंडी स्टेट न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है, बल्कि समाजसेवा और जनसहयोग की भावना के लिए भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध है।उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित झंडी स्टेट के वर्तमान राजा राज राजेश्वर सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विदेश संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक भी हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि राजमहल में पहुंचने वाला कोई भी फरियादी आज तक निराश होकर वापस नहीं लौटा।

समय बताने के लिए घंटा बजाता राजमहल का कर्मचारी

झंडी गांव में स्थित राजमहल की सबसे अनोखी परंपरा है घंटा बजाकर पूरे गांव को समय बताना। तकनीक और डिजिटल युग के बावजूद यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है।

गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि राजमहल का घंटा विशेष धातु से निर्मित है, जिसकी आवाज केवल झंडी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती है।

ग्रामीणों के अनुसार दिन में जितना समय होता है, उतनी ही बार घंटा बजाया जाता है। यदि दोपहर के बारह बजे हैं तो घंटा बारह बार बजेगा। गांव के कई बुजुर्ग आज भी इसी घंटे की आवाज के आधार पर अपनी दिनचर्या तय करते हैं। मोबाइल और घड़ी से दूर रहने वाले ग्रामीणों के लिए यह घंटा आज भी समय का सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है।झंडी राजपरिवार का इतिहास केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजहित के कार्यों से भी जुड़ा रहा है। राजपरिवार द्वारा लखनऊ नगर निगम को दान में दी गई बेशकीमती जमीन पर आज प्रसिद्ध ÷झंडी पार्क÷ स्थित है, जो राजधानी के लालबाग क्षेत्र की पहचान बना हुआ है। इसके अलावा राजपरिवार द्वारा बनवाए गए कई मंदिर आज भी लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। वर्तमान में झंडी राजपरिवार में राजमाता सहित तीन पुत्र राज राजेश्वर सिंह, विजय राज सिंह और अजय राज सिंह परिवार की विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बदलते समय के बीच झंडी राजमहल आज भी इतिहास, संस्कृति और समाजसेवा की जीवंत मिसाल बना हुआ है।

झंडी राजमहल

कु0 विजय राज सिंह

कु0 अजय राज सिंह

झंडी स्टेट की राजमाता, भक्ति देवी

वर्तमान राजा राज राजेश्वर सिंह

खास ख़बर

अयोध्या में सरयू बनी मौत का दरिया
स्नान के दौरान तीन युवक डूबे

» जन्मदिन मनाने बस्ती से आए थे पांच दोस्त, डूबे युवकों की तलाश जारी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो।

अयोध्या। अयोध्या में गुरुवार सुबह सरयू नदी में स्नान के दौरान तीन युवकों के लापता होने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जल पुलिस, गोताखोर और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार युवकों की तलाश में जुटी हैं।घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।जानकारी के मुताबिक बस्ती जनपद के पांच दोस्त गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अयोध्या पहुंचे थे। सभी युवक दर्शन-पूजन के साथ एक दोस्त का जन्मदिन मनाने आए थे।मंदिरों में दर्शन से पहले उन्होंने सरयू नदी में स्नान करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि जलस्तर कम होने के कारण नदी किनारे काफी दूर तक रेत फैली हुई थी। इसी दौरान तीन युवक घाट से काफी अंदर तक चले गए और स्नान करने लगे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान करते समय युवकों को नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लग सका और देखते ही देखते तीनों पानी में डूब गए। काफी देर तक वापस न लौटने पर उनके साथ आए दो दोस्तों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि लापता युवकों की पहचान अभिषेक कुमार सोनी (19) पुत्र शंभू, अमित (20) पुत्र राजेश और राज गुप्ता (20) के रूप में हुई है। सभी बस्ती जनपद के मंगल बाजार पुरानी बस्ती क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि गोताखोरों की मदद से सरयू नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद हैं और हर संभावित स्थान पर तलाश की जा रही है। वहीं, घटना के बाद साथ आए दोनों युवक भी सदमे में हैं। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं।परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके अयोध्या पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है और जल्द युवकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

थाना सोता रहा, दबंग तोड़ते रहे हड्डियां!

पहले दी गई थी हत्या की चेतावनी, फिर भी नहीं जागी पुलिस

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र में हुई खूनी वारदात ने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि 27 अप्रैल को ही पीड़ित परिवार ने ऑनलाइन शिकायत देकर साफ चेतावनी दी थी कि उनके परिवार पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। लेकिन थाना महाराजगंज पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया, और फिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई गई थी।3 मई की सुबह टहलने निकले महेश तिवारी पर कथित दबंगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि सड़क पर दौड़ाकर उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फायरिंग करते हुए आरोपी फरार हो गए। हमले में महेश तिवारी के दोनों हाथ टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आईं। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है।

अगर पहले से शिकायत मौजूद थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्या पुलिस किसी की मौत का इंतजार कर रही थी? पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस कार्रवाई से बचती रही। अब देखना होगा कि अयोध्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा।

अयोध्या में नजूल माफिया का नया खेल!

» खिड़की लगाने पहुंचा परिवार, सामने आ गया कब्जे का साम्राज्य

» पीड़ित परिवार बोला, नजूल अफसर और लेखपाल की मिलीभगत से बने फर्जी कागज

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

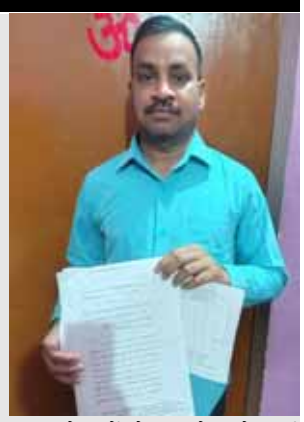

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में नजूल विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बेनीगंज चौराहे पर एक परिवार ने जब अपने मकान में रोशनी के लिए दूसरी मंजिल पर खिड़की लगाने की कोशिश की तो मामला सीधे कथित नजूल खेल तक पहुंच गया।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके मकान के पीछे मौजूद करीब पांच फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करा दिया गया और अब उसी कब्जे को बचाने के लिए दबाव, धमकी और गाली-गलौज का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप नजूल विभाग के अफसरों और एक चर्चित लेखपाल पर लगा है। परिवार का दावा है कि सार्वजनिक रास्ते को कागजों में गायब करने और फर्जी अभिलेख तैयार कराने में विभागीय मिलीभगत हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में नजूल जमीन और सार्वजनिक रास्तों का ÷मास्टरमाइंड÷ कौन है?कौन है वह लेखपाल जिसके इशारे पर सरकारी जमीनें कागजों में इधर से उधर हो जाती हैं? सूत्र बताते हैं कि नजूल विभाग में वर्षों से एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है, जो पहले कब्जा करवाता हैज फिर कागज तैयार करता है और बाद में पीड़ित को ही आरोपी बना देता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि क्षेत्र में वह अकेला हिंदू परिवार है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी इस मामले में नजूल विभाग की भूमिका की जांच कराते हैं या फिर सरकारी जमीन और रास्तों का खेल यूं ही चलता रहेगा।

रामनगरी से उठी 2027 की चुनावी हुंकार

बंगाल विजय के बाद भाजपा ने
अयोध्या से फूंका यूपी फतह का बिगुल

» राम मंदिर, महिला वोट और बूथ मैनेजमेंट के सहारे भाजपा का मिशन हैट्रिक तेज

» सपा जातीय समीकरण में उलझी, भाजपा हर घर-हर मतदाता फार्मूले पर आगे

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार कब्जा जमाने की रणनीति तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन को भाजपा की 2027 चुनावी रणभेरी माना जा रहा है और इस पूरे राजनीतिक अभियान का केंद्र बन चुकी है रामनगरी अयोध्या।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां विकास और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रहे हैं, वहीं संगठन स्तर पर बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों और शक्ति केंद्रों की मजबूत फौज खड़ी की जा रही है। भाजपा अब महिला आरक्षण, लाभार्थी वर्ग और हिंदुत्व के सहारे जातीय समीकरणों को तोड़ने की तैयारी में है।

पीएम मोदी, शाह और बंसल की रणनीति से हुई बंगाल विजय

नगर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की रणनीति ने बंगाल में इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भाजपा अब राम मंदिर संगठन लाभार्थी मॉडल पर यूपी चुनाव लड़ने जा रही है। जल्द होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार भी इसी सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जा रहा है।

भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं, जनता का विश्वास जीतती है

भाजपा जिला मंत्री शिवेंद्र सिंह ने कहा कि बंगाल की जीत राष्ट्रवाद और मजबूत संगठन की जीत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से निकला विकास और हिंदुत्व का संदेश अब पूरे देश में असर दिखा रहा है और 2027 में भाजपा फिर इतिहास रचेगी।

नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता

शिवेन्द्र सिंह-जिला मंत्री

सवालों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन

शासनादेश ठंडे बस्ते में : राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम व्यवस्था अब भी ठप

» एमओयू हुआ, आदेश जारी हुए, लेकिन फॉरेंसिक ड्यूटी से अब भी दूरी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पोस्टमार्टम सुविधा शुरू करने का स्पष्ट आदेश जारी किया था, ताकि फॉरेंसिक शिक्षा मजबूत हो, जिला अस्पतालों का बोझ कम हो और शव परीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। लेकिन राजर्षि दशरथ स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या में शासनादेश अब भी फाइलों में कैद दिखाई दे रहा है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि पोस्टमार्टम हाउस अभी नहीं बना है, इसलिए व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही। जबकि सच्चाई यह है कि मेडिकल कॉलेज ने जिला अस्पताल की मर्चरी से एमओयू कर रखा है। सीएमओ ने 2 फरवरी 2026 को सशर्त अनुमति देते हुए स्पष्ट कहा था कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया में नियमित फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी अनिवार्य होगी और मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग से किसी डॉक्टर की नियमित पोस्टमार्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा रही।

सूत्रों के मुताबिक विभागाध्यक्ष डॉ. अंजू सिंह पोस्टमार्टम ड्यूटी नहीं करना चाहतीं, जबकि वह इस व्यवस्था की प्रमुख कड़ी मानी जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासनादेश, एमओयू और सीएमओ की शर्तें मौजूद हैं, तो आखिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन किसके संरक्षण में नियमों को नजरअंदाज कर रहा है? इस लापरवाही का खामियाजा न सिर्फ मेडिकल छात्रों को, बल्कि न्याय की उम्मीद लगाए बैठे आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है।

आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से की मुलाकात

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) अयोध्या के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में नवागत जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।आईएमए पदाधिकारियों ने आईएमए भवन निर्माण में आ रही समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान डॉ. आशीष श्रीवास्तव, डॉ. निशांत सक्सेना, डॉ. आर.के. बनौधा सहित अन्य चिकित्सक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

सीमा पर सख्ती, ढाका में बढ़ी बेचैनी

असम-बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बांग्लादेश सतर्क, 'पुशबैक' और घुसपैठ पर बढ़ी चिंता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल तेज हो गई है। ढाका को आशंका है कि सीमावर्ती राज्यों में बीजेपी की मजबूत वापसी के बाद भारत अवैध प्रवासियों और सीमा पार गतिविधियों के खिलाफ और सख्त नीति अपना सकता है। इसी संभावना को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सीमा सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने राजधानी ढाका में आयोजित जिलाधिकारियों के सम्मेलन के बाद कहा कि सरकार ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी बड़े तनाव की आशंका नहीं है, लेकिन भारत की नई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध और कथित बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी यानी 'पुशबैक' का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। चुनावी अभियानों में भी यह विषय लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा। ऐसे में बीजेपी की चुनावी सफलता के बाद ढाका में यह चिंता गहरा गई है कि नई दिल्ली सीमा प्रबंधन और नागरिक सत्यापन को लेकर और कड़ा रुख अपना सकती है।

इस बीच बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी की ओर से भी बयान सामने आया है। पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेश मंत्री खलीलुर्रहमान के हवाले से कहा गया कि यदि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को जबरन भेजने जैसी कार्रवाई होती है, तो ढाका आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाएगा।

दोनों देशों के रिश्तों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा भी तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है। वर्ष 2024 में सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है, हालांकि इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इससे दोनों देशों के संबंधों में एक अतिरिक्त संवेदनशीलता जुड़ गई है। हालांकि भारत सरकार ने रिश्तों को सामान्य बनाए रखने के संकेत दिए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने हाल ही में बांग्लादेशी पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में कहा कि दोनों देशों ने हाल के समय में कठिन दौर देखा है, लेकिन अब द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, ऊर्जा सहयोग और कांसुलर मामलों को लेकर 40 से अधिक द्विपक्षीय तंत्र सक्रिय हैं। इनमें तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता भी शामिल है, जो वर्षों से राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। अब असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद क्षेत्रीय राजनीति और सीमा सुरक्षा का असर एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों पर साफ दिखाई देने लगा है।

शेख हसीना विवाद से बढ़ी संवेदनशीलता

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका की अंतरिम सत्ता लगातार दबाव बना रही है। यही कारण है कि दोनों देशों के रिश्तों में राजनीतिक अविश्वास बढ़ा हुआ है।

तीस्ता समझौता फिर चर्चा में क्यों?

तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता वर्षों से लंबित है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इसमें अहम भूमिका निभाती रही है। नई राजनीतिक परिस्थितियों में इस मुद्दे पर नई बहस तेज हो सकती है।

- भारत-बांग्लादेश सीमा लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी है।
- पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है।
- असम में अवैध घुसपैठ हमेशा बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है।
- बीजीबी और बीएसएफ के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग होती रहती है।
- तीस्ता जल समझौता अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है।
- शेख हसीना के भारत में रहने से ढाका की राजनीति संवेदनशील बनी हुई है।
- सीमा सुरक्षा और नागरिकता का मुद्दा आने वाले समय में फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन सकता है।

'पुशबैक' आखिर है क्या?

सीमा पार अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर वापस भेजने की कार्रवाई को 'पुशबैक' कहा जाता है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर यह मुद्दा वर्षों से राजनीतिक और मानवीय बहस का हिस्सा रहा है।

क्यों अहम हैं बंगाल और असम?

दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं। घुसपैठ, तस्करी और सीमा सुरक्षा के अधिकांश मामले इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं। इसलिए यहां की राजनीतिक स्थिति सीधे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है।

सीमा सुरक्षा पर बढ़ेगा फोकस

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत सीमा निगरानी, नागरिक सत्यापन और डिजिटल सर्विलांस को और मजबूत कर सकता है। इसका असर सीमावर्ती जिलों में साफ दिखाई देगा।

अमेरिका-ईरान 'शांति डील' के बेहद करीब

20 साल की दुश्मनी खत्म करने की तैयारी!

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिका और ईरान अब एक ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौते के बेहद करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्ति और परमाणु विवाद के समाधान को लेकर एक पेज के अहम एमओयू पर अंतिम स्तर की सहमति बन रही है। यदि यह समझौता लागू हो जाता है तो इसे इस सदी की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक डील माना जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित समझौते में 14 सूत्रीय ढांचा तैयार किया गया है, जिसका मकसद तत्काल युद्धविराम लागू करना और अगले 30 दिनों के भीतर व्यापक परमाणु समझौते तक पहुंचना है। इसके तहत ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगाने को तैयार हुआ है। बदले में अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने और विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

➪ **14 सूत्रीय समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत, युद्धविराम से लेकर परमाणु कार्यक्रम तक बन रहा बड़ा रोडमैप**

समझौते का बड़ा फोकस होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करना भी है। दोनों देश समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने और जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करने पर सहमत होते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में होर्मुज क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां सीमित करने का फैसला भी इसी बैकडोर कूटनीति का हिस्सा है।

बताया जा रहा है कि इस पूरी वार्ता की अगुवाई अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं। दोनों प्रत्यक्ष और तीसरे पक्ष के माध्यम से तेहरान के संपर्क में हैं। अगर समझौता अंतिम रूप लेता है तो इसे औपचारिक रूप से "युद्ध समाप्ति घोषणा" माना जाएगा। इसके बाद तकनीकी स्तर की वार्ताएं जिनेवा या इस्लामाबाद में आयोजित हो सकती हैं।

हालांकि कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति बाकी है। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाई जाने वाली रोक की अवधि को लेकर है। अमेरिका 20 वर्षों की सीमा चाहता है, जबकि ईरान केवल 5 वर्षों तक की शर्त मानने को तैयार बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्ष 12 से 15 वर्षों के बीच किसी मध्य रास्ते पर सहमत हो सकते हैं।

प्रस्तावित ढांचे में ईरान को भविष्य में केवल 3.67 प्रतिशत तक सीमित यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने पर भी चर्चा है। इसके बदले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने की ठोस गारंटी देनी होगी। भूमिगत परमाणु ठिकानों पर रोक, संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों की अचानक जांच और उच्च स्तर के यूरेनियम भंडार को हटाने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मारको रुबिओ ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन प्रारंभिक शर्तों और रियायतों की स्पष्ट सीमाएं तय करना जरूरी होगा। दुनिया की नजर अब अगले 48 घंटों पर टिकी है, जो इस संभावित समझौते के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com